और किसानों को लाभकर मूल्य प्राप्त हो, इस तरह उनकी सहायता करने की बात को ध्यान में रखकर, 3 अक्तूबर, 1988 से दालों पर आयात शुल्क को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 35 प्रतिशत कर दिया गया था।

(ख) से (घ) दिल्ली आनाज व्यापारी संघ ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उसने दालों पर आयात शुल्क को हटाने के लिए अनुरोध किया है। दालों पर आयात शुल्क को कम करने के लिए सरकार पर्याप्त औचित्य नहीं देखती है।

भारत में पाकिस्तान की इन्टर सर्विसिज इन्टेलीजेंस एजेंसी की गतिविधियां

1029. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तानी समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की इन्टर सर्विसिज इन्टेलीजेंस एजेंसी भारत में सक्रिय रही थी और इस एजेंसी के लिये पाकिस्तानी सरकार द्वारा धनराशि मंजूर की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारत में पाकिस्तान की "इन्टर सर्विसिज इन्टेलिजेंस" की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से अभिस्वीकृत करने से संबंधित कोई प्रेस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आयी है। तथापि 18 जून, 1989 के पाकिस्तानी दैनिक "दी नेशन" में प्रकाशित एक लेख में आई. एस. आई. के घटे हुए स्तर पर टिप्पणी की गई है। इस लेख में कहा गया है कि भारत में प्रचालन कार्रवाईयां समाप्त कर दी गई हैं और इसे पैसा देना बंद कर दिया गया है। इससे यह भाव निकाला जा सकता है कि आई.एस.आई. भारत में सक्रिय थी और पाकिस्तान सरकार द्वारा इसे धनराशि मंजूर की जाती थी। सरकार देश की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे के बारे में भली भांति अवगत है।

Irregularities committed in Indore branches State Bank of Indore

1030. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of branches of the State Bank of Indore operating at Indore and the number of cases regarding bungling/irregularities committed in these branches brought to light during the last three years and upto 30 June, 1989;

(b) the details of the amount involved in these cases; anl

(c) the number of officers/employees found guilty and the action taken in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) Information is being collected and to the extent available, will be laid on the Table of the House.

Filling up of SC/ST vacancies in the office of the development Commissioner, Delhi Administration

1031. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the latest Government policy, all vacancies of SC and ST must be filled up within the stipulated time;

(b) if so, what are the reasons for which the candidates belonbing to the